खबरें

RNI : MAHHIN/2003/10991

आप तक

वर्ष - 24 अंक -04 मुंबई, सोमवार ९ फरवरी से १५ फरवरी २०२६ पृष्ठ : 4 कीमत : 1 रुपये

गंदगी करने वालों की खैर नहीं बीएमसी ने तैयार किया बीट मार्शल

मुंबई : बीएमसी ने शहर में गंदगी करने वालों पर करने के लिए जूनियर सुपरवाइजर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। जूनियर सुपरवाइजर को बीट मार्शल के रूप में पहचान होगी। बीट मार्शल के पास दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उनके पास हैंड डिवाइस मशीन रहेगा, जिससे दंड वसूल कर उसकी रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि शहर में गंदगी फैलाने वालों पर अब कठोर कार्रवाई करने का निणर्य मनपा प्रशासन ने लिया है। बीएमसी ने बड़े नीतिगत बदलाव के तहत विवादित ''क्लीन-अप मार्शल'' योजना को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। वर्षों से इस योजना को लेकर वसूली और दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही थीं। निजी ठेकेदारों की जगह अब बीएमसी अपने 350 जूनियर सुपरवाइजर (खर) को शहर के 24 वाडों में तैनात करेगी। जिसके तहत गन्दगी करने वालों से दंड वसूली की जाएगी। बीएमसी द्वारा गंदगी फैलाने वाले सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, थूकने और खुले में कचरा डालने जैसे मामलों में जुमार्ना लगाने का

अधिकार दिया गया है। इस तरह की जानकारी मनपा उपायुक्त किरण दिघावकर ने दी। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए निजी क्लीन-अप मार्शलों की जगह अब बीएमसी के कर्मचारी पुलिस के बीट मार्शल की तरह काम करेंगे और प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सभी कर्मचारी बीएमसी के स्थायी कर्मचारी होंगे और उनके पास आधिकारिक पहचान पत्र होगा।

केवल अधिकृत कर्मचारी ही रसीद के साथ जुमार्ना वसूल सकेंगे, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

अधिकारियों के अनुसार निजी क्लीन-अप मार्शल योजना अप्रैल 2025 में बंद कर दी गई थी और लंबी चर्चा के बाद इसे स्थायी रूप से समाप्त कर बीएमसी के अपने कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। तैनाती से पहले सभी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें जनता से विनम्र व्यवहार और नियमों की सही जानकारी शामिल होगी।

मुंबई झुग्गी पुनर्वास विवाद: राज्य सरकार-MCGM को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश को बताया चुनौतीपूर्ण...

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई नगर निगम और झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण सहित अन्य पक्षकारों से बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद आदेश के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा। यह याचिका उन प्लॉट्स पर पुनर्वास योजनाओं को चुनौती देती है, जो मूल रूप से पार्क, उद्यान और खेल मैदान के लिए आरक्षित थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 जून 2025 को डीसीपीआर 2034 के रेगुलेशन17(3)(डी)(2) को वैध ठहराते हुए कहा था कि यह नियम उपनगरीय झुग्गी पुनर्वास योजनाओं

को लागू करने की अनुमति देता है, बशर्ते जनता के लिए एक हिस्से को पुनः हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संतुलन मुंबई की हरित आवरण आवश्यकता और आवास के संवैधानिक अधिकार के बीच है।

हाईकोर्ट ने जारी किए थे 17-सूत्रीय सख्त दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची ने वरिष्ठ वकील श्याम दिवान के तर्कों को नोट किया। दिवान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई में खुले सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा जरूरी है।

हाईकोर्ट की बेंच ने हालांकि नियम की वैधता को स्वीकार करते हुए 17-सूत्रीय सख्त दिशानिर्देश जारी किए ताकि वादित खुली जगहें केवल कागज पर न रहकर वास्तविक, सार्वजनिक रूप से सुलभ सुविधाएं बनें।

हाई कोर्ट ने गायब पेड़ों के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

मुंबई : नगर निगम ने शहर में अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 6,300 से ज्यादा पेड़ काटने की इजाजत दी है; हालांकि, इसके बदले में संबंधित लोगों ने 89,000 से ज्यादा नए पेड़ नहीं लगाए हैं। इस वजह से शहर की हरियाली 31 प्रतिशत से घटकर सिर्फ.12 प्रतिशत रह गई है।

इसके अलावा, शहर में 2011 के बाद से पेड़ों की गिनती नहीं हुई है। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस जानकारी पर ध्यान देते हुए मंगलवार को राज्य सरकार और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया

और उन्हें चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। इस संबंध में एक सामाजिक संगठन, स्वच्छ एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की बेंच के सामने सुनवाई हुई। नगर निगम की ट्री अथॉरिटी गैर-कानूनी तरीके से काम कर रही है।

महाराष्ट्र में सड़क हादसों का कहर जारी, लगातार छठे साल बढ़ी दुर्घटनाएं; 2025 की मौतों का आंकड़ा आया सामने

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा को लेकर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या में लगातार छठे वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, 2025 में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 2021 के बाद पहली बार मामूली कमी देखी गई है, जिससे राहत के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग द्वारा जारी वर्ष 2025 के अनंतिम सड़क दुर्घटना आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बढ़ते वाहन पंजीकरण, तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के चलते सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में वर्ष 2025 के दौरान कुल 36,450 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। यह संख्या न केवल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, बल्कि यह लगातार छठी वार्षिक वृद्धि को भी दशार्ती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में राज्य में 24,971 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इसके बाद 2021 में यह

संख्या बढ़कर 29,477 हो गई। वर्ष 2022 में दुर्घटनाओं की संख्या 33,383 तक पहुंच गई, जबकि 2023 में 35,243 और 2024 में 36,110 सड़क हादसे दर्ज किए गए। वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 36,450 हो गया है, जो राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 4.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में सड़कों की क्षमता, ट्रैफिक प्रबंधन और जन-जागरूकता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

मौतों के आंकड़ों में मामूली गिरावट

हालांकि, इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि महाराष्ट्र 2021 के बाद पहली बार सड़क हादसों में मौतों की संख्या में मामूली कमी लाने में सफल रहा है। वर्ष 2025 में राज्य में 14,440 घातक दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 15,549 लोगों की मौत हुई। इसके मुकाबले वर्ष 2024 में 14,565 घातक दुर्घटनाओं में 15,715 लोगों की जान गई थी। आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में वर्ष 2020 के बाद लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। वर्ष 2020 में सड़क हादसों में कुल 11,569 लोगों की जान गई थी। इसके बाद 2021 में यह संख्या बढ़कर 13,528 हो गई। वर्ष 2022 में 15,224, 2023 में 15,366 और 2024 में 15,715 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में दर्ज की गई थी। ऐसे में 2025 में मौतों की संख्या में आई मामूली गिरावट को विशेषज्ञ सतर्क आशावाद के तौर पर देख रहे हैं।

हालांकि, गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों की संख्या के मामले में राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या को कम करने में विफल रहा है। वर्ष 2025 में कुल 23,756 लोग सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 2024 में ऐसे मामलों की संख्या 22,051 थी। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में सड़क हादसों में 13,971 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यह संख्या 2021 में बढ़कर 16,073 हो गई।

संपादकीय

भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी

मलेशिया के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में बताया है. उन्होंने कहा कि यह बात ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हाल में हुए व्यापार समझौतों में परिलक्षित होती है. कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय के लोगों को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शनिवार (7 फरवरी, 2026) को कहा कि भारतीय प्रवासी भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं. विभिन्न देशों के साथ भारत की ओर से किए गए व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जाता है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (वअए), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ (एव) और अमेरिका के भारत के साथ व्यापारिक समझौते हुए हैं और विश्वास भारत की सबसे मजबूत मुद्रा बन गया है.

पीएम मोदी ने कहा, ह्यहम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसका कारण हमारी भाषाओं और मलय भाषा में बड़ी संख्या में मौजूद समान शब्द ही होंगे. कुआलालंपुर में भारतीय प्रवासियों के स्नेह के लिए मैं आभारी हूं. हमारा प्रवासी समुदाय भारत और मलेशिया के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता आ रहा है.ह्ल

उन्होंने कहा कि उन्हें मलेशिया में आकर बहुत खुशी हो रही है, जो 2026 में उनकी पहली विदेश यात्रा है. उन्होंने कहा, ह्यमलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही दोस्त हैं.ह्ल पीएम मोदी ने कहा, ह्यभारत हमेशा आपका खुले दिल से स्वागत करेगा. इसीलिए, कुछ महीने पहले ही हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिकों को छठी पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड के लिए पात्र घोषित किया है.ह्ल

मोदी ने पर एक पोस्ट में कहा, ह्यभारतीय सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड की पात्रता को छठी पीढ़ी तक के भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिकों तक विस्तारित करने के निर्णय से प्रवासी मलेशियाई लोगों में अपार खुशी का माहौल है. आने वाले समय में मलेशिया में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा, जिससे हमारे राष्ट्र और भी करीब आ जाएंगे.ह्ल उन्होंने कहा, ह्यमलेशिया में रहने वाले तमिल प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं. दरअसल, तमिल प्रवासी यहां कई सदियों से रह रहे हैं. इस इतिहास से प्रेरित होकर, हमें मलय विश्वविद्यालय में तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना करने पर गर्व है. अब हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करने के लिए एक तिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करेंगे.ह्ल मोदी ने कहा कि विश्व में भारतीय मूल के लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मलेशिया में है और भारतीय और मलेशियाई लोगों के दिलों को जोड़ने वाली कई बातें हैं. उन्होंने कहा कि मैंने हाल में अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान 1.4 अरब भारतीयों के साथ साझा किया था कि मलेशिया में 500 से अधिक स्कूल बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाते हैं. पीएम मोदी ने कहा, ह्यभारत की सफलता मलेशिया की सफलता है और यह एशिया की सफलता है. इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे संबंधों का मार्गदर्शक शब्द इम्पैक्ट है. इम्पैक्ट का अर्थ है सामूहिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए भारत-मलेशिया साझेदारी.ह्ल मोदी ने भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों से भारत की यात्रा करने और भारत का अनुभव करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा, ह्यआपको अपने मलय मित्रों को भी साथ लाना होगा. क्योंकि लोगों के बीच संपर्क ही हमारी मित्रता की आधारशिला है.ह्ल वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस मौके पर कहा, ह्यभारत से एक अच्छे मित्र के मलेशिया में हमारे साथ शामिल होने से मैं व्यक्तिगत रूप से उत्साहित हूं.ह्ल उन्होंने दोनों देशों के बीच प्राचीन संबंधों को याद किया. उन्होंने कहा, ह्यभारत, मलेशिया के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है. हमारे बीच न केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, बल्कि 2025 में 15 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक मलेशिया आए थे.ह्ल उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी और भारत का मित्र होने पर गर्व है.

संपादकीय कार्यालयः
आर. जे. पब्लिकेशन के लिए मुद्रक, प्रकाशक, मालिक राजू ज. पंडित द्वारा हनुमान कंपाउंड, एस.एन. दुबे रोड, रावल पाडा, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400068 से प्रकाशित व भारत लिथो एवं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस : 48, गुलशन महल कंपाउंड, फारस रोड, मुंबई - 400008 से मुद्रित। संपादक : राजू ज. पंडित
संपर्क कार्यालय : संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो.लि. एसएन दुबे रोड रावल पाड़ा दहिसर (पूर्व) मुंबई 400068

संपर्क कार्यालय : एकता नगर हा. सो. लि., एस एन दुबे रोड
रावलपाड़ा दहिसर पूर्व मुंबई ४०००६८
Mob No. : 9967776303
RNI : MAHHIN/2003/10991

मुंबई : अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस पर बुलिश मॉर्गन स्टेनली दिया, 1,133 रुपए का टारगेट प्राइस

मुंबई : ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर की कवरेज शुरू कर दी है और 'ओवरवेट' रेटिंग के साथ 1,133 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है एईएसएल को भारत में लंबी अवधि में होने वाले पावर ग्रिड में विस्तार से फायदा मिलेगा। साथ ही कहा कि अगले एक दशक में देश में 10 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन निवेश होने की संभावना है। कंपनी के वितरण कारोबार पर ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया कि स्मार्ट मीटरिंग पर सरकार के समर्थन, जिसमें सब्सिडी शामिल है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने एईएसएल के मजबूत एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें समय पर और लागत-कुशल परियोजना वितरण का हवाला दिया गया है। फर्म ने ट्रांसमिशन, वितरण और स्मार्ट मीटरिंग में कंपनी की एकीकृत उपस्थिति हासिल की है, जो इसे एक संपूर्ण ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित करती है।

मॉर्गन स्टेनली ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को ट्रांसमिशन और वितरण में अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी बताया है, जिसकी निजी क्षेत्र के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, मुंबई और मुंद्रा एसईजेड वितरण क्षेत्रों के माध्यम से लगभग 33 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंच है और स्मार्ट मीटरिंग में इसकी मजबूत उपस्थिति है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 से 2030 के बीच ईबीआईटीडीए में 21 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2030 तक ईबीआईटीडीए लगभग 2,600 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि ट्रांसमिशन परियोजनाओं की जीत, विनियमित वितरण पूंजीगत व्यय और स्मार्ट मीटरिंग ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन से प्राप्त होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में निकट से मध्यम अवधि में ट्रांसमिशन को सबसे मजबूत विकास चालक के रूप में पहचाना गया है, जिसे वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही तक लगभग 7,800 करोड़ रुपए के मौजूदा ऑर्डर बुक का सपोर्ट प्राप्त है। मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि एईएसएल नई टीबीसीबी परियोजनाओं में से लगभग 20 प्रतिशत जीत सकती है, जो प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए के संभावित अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्ट में वितरण क्षेत्र में समानांतर लाइसेंसिंग से उत्पन्न अवसरों के बार में बताया गया है, जिसमें एईएसएल का लक्ष्य 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। कंपनी के रेगुलेटेड एसेट बेस में लगभग 11 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि होने का अनुमान है, जिसे लगभग 1,600 करोड़ रुपए के वार्षिक पूंजीगत व्यय का समर्थन प्राप्त है। स्मार्ट मीटरिंग में, एईएसएल का लक्ष्य लगभग 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। इसके 24.6 मिलियन मीटर के ऑर्डर बुक का अधिकांश हिस्सा वित्त वर्ष 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें स्मार्ट मीटरिंग का योगदान वित्त वर्ष 2028 के ईबीआईटीडीए में लगभग 9 प्रतिशत होगा, जिसमें गैर-आईएफआरएस समायोजन शामिल नहीं हैं।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई की मौत के मामले में अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज कर दी...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम को अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित अपने पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।सलेम 23 साल से अधिक समय से जेल में है। 12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बॉम्बे सीरियल बम धमाकों के मामले में प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया और उससे अपने इस दावे को सही ठहराने को कहा कि उसने अपनी आजीवन कारावास की सजा के 25 साल पूरे कर लिए हैं।

दोषी व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उसकी सजा माफी की याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दे रहा था।इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी थी।

अबू सलेम वर्तमान में 1993 के मुंबई बम धमाकों और अन्य मामलों में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह जेल में है। 18 सितंबर 2002 को अबू सलेम को लिस्बन (पुर्तगाल) में हिरासत में लिया गया। लिस्बन की अपील अदालत और पुर्तगाल के संवैधानिक न्यायालय में लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद, अबू सलेम के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई और 10 नवंबर 2005 को उनकी हिरासत भारतीय अधिकारियों को सौंप दी गई।

मुंबई : सिविल सर्जन ने कैंसर जागरूकता बढ़ाई...

मुंबई : आम रोजमर्रा की दौड़ भाग की जिंदगी में बढ़ती लापरवाही व अनियमितता, तंबाकू की लत का बढ़ता चलन और हेल्थ चेक-अप पर ध्यान न देना कैंसर के बढ़ने के मुख्य कारण बताते हुए, ''कैंसर कोई मौत की सजा नहीं है; यह एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पता चलने पर पूरी तरह से इलाज हो सकता है। ठाणे जिला सिविल सर्जन डॉ पवार कैंसर रोग फैलने से पहले समय पर संदिग्ध शख्स को उसकी जांच करनी चाहिए।कहना है कि हालांकि, डर, अफवाहों और ध्यान न देने की वजह से कई जानें खतरे में हैं। इसलिए, हर नागरिक को अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक और सावधान रहना जरूरी है, ।

वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर ठाणे जिला सिविल अस्पताल में कैंसर अवेयरनेस और गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया गया। इस मौके पर डॉ. कैलाश पवार चीफ गाइड के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में, उन्होंने कैंसर के शुरूआती लक्षणों, बचाव के तरीकों, मॉडर्न इलाज के तरीकों के बारे में डिटेल में जानकारी दी और बताया कि समय पर डायग्नोसिस से इलाज का सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। ''अगर आपको कोई फिजिकल बदलाव, दर्द या असामान्य लक्षण दिखें, तो उन्हें छिपाएं नहीं; उन्होंने अपील की, ''तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।''

इस प्रोग्राम के दौरान, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. हितेश सिंघवी, डेंटल सर्जन डॉ. अर्चना पवार ने ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर जैसी बीमारियों पर खास गाइडेंस दी। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं और युवाओं के लिए रेगुलर चेक-अप को आदत बनाना समय की जरूरत है। प्रोग्राम के दौरान, एक्सपर्ट डॉक्टरों ने मौजूद लोगों को गाइडेंस दी और कैंसर से बचाव और इलाज पर ब्रोशर बांटे गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ. धीरज महानगड़े, डेंटल सर्जन डॉ. अर्चना पवार, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. हितेश सिंघवी, डॉ. रितिका भंडारी, सारंगी महाजन वगैरह के साथ-साथ हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर, कर्मचारी, मरीज और लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।

पार्थ पवार को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, बल्कि उनकी जांच अभी भी जारी है - अंजलि दमानिया

मुंबई : पार्थ पवार को पुणे लैंड स्कैम में क्लीन चिट मिलने की खबरें मीडिया में आई थीं। इस पर सोशल एक्टिविस्ट्स ने नाराजगी जताई है। अंजलि दमानिया ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। पार्थ पवार को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, बल्कि उनकी जांच अभी भी जारी है, दमानिया ने एक बार फिर इस मामले पर बात करते हुए यह बताया। दमानिया ने सवाल उठाया है, ''यह रिपोर्ट मीडिया तक कैसे पहुंची? क्योंकि रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है और इसे जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में आखिरी मीटिंग अभी होनी बाकी है।'' दमानिया ने सबूत के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रिंटआउट जमा किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शीतल तेजवानी और पार्थ पवार के बीच हुए एग्रीमेंट में पार्थ पवार का नाम, सिग्नेचर और मुहर है।

मुंबई : म्हाडा की 120 फ्लैट्स की लॉटरी, पहले आओ पहले पाओ से मौका...

मुंबई : मुंबई में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने मुंबई के अलग-अलग इलाकों में 120 फ्लैट्स बेचने का ऐलान किया। इस स्कीम की खासियत यह है कि ये घर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक, इन घरों की कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं। साउथ मुंबई के ताड़देव में सबसे महंगे अपार्टमेंट की कीमत 8 करोड़ से ज्यादा है। जबकि सबसे सस्ते घर की कीमत 38 लाख है।

फ्लैट की लोकेशन कहां है?

म्हाडा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये फ्लैट्स मुंबई के कई जरूरी इलाकों जैसे कांदिवली, चारकोप, वडाला, पवई, ताड़देव, जुहू और अंधेरी में हैं। इन फ्लैट्स के लिए लॉटरी कुछ दिन पहले हुई थी। लेकिन किसी वजह से यह फ्लैट नहीं बिका। अब इन्हें 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिक्री के लिए रखा गया है। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी गुरुवार, 5 फरवरी, 2025 को म्हाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गया है। इसके बाद, एप्लीकेंट अपनी पसंद का फ्लैट चुन सकते हैं और 12 फरवरी, 2026 से सिक्योरिटी डिपॉजिट और एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं।

आवेदन के समय क्या जरूरी?

वेबसाइट पर फ्लैट चुनने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर घर की कुल कीमत का 10 परसेंट जमा करना होगा। यह पेमेंट मिलने पर म्हाडा आपको बाकी रकम के लिए एक प्रोविजनल 'ऑफर लेटर' जारी करेगा। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आप 48 घंटे के अंदर यह 10% रकम जमा नहीं करते हैं। तो आपका क्लेम कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

म्हाडा ने असल में क्या कहा?

म्हाडा ने साफ किया कि अगर कोई एप्लीकेंट 'प्रोविजनल ऑफर लेटर' मिलने के बाद किसी भी वजह से फ्लैट कैंसिल करता है या तय समय के अंदर पूरी कीमत जमा नहीं करता है। फिर फ्लैट की कुल कीमत का 1% पेनल्टी काट ली जाएगी। बाकी रकम बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला प्री-अप्रूवल लेटर अपनी लॉगिन क्क से अपलोड करना होगा। उसके बाद म्हाडा उसी लॉगिन क्क का इस्तेमाल करके बैंक को एनओसी जारी करेगा। फ्लैट की पूरी कीमत और स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद म्हाडा एप्लीकेंट को अलॉटमेंट और पजेशन लेटर जारी करेगा।

शराबी पति ने पत्नी को पीटा... पति पर केस दर्ज

भिवंडी : भिवंडी शहर में शराब को लेकर हुए घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां पत्न ी द्वारा पति को दारू पीने से मना करना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुस्से में आए पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद महिला की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार घटना 4 फरवरी की सुबह करीब 9.30 बजे धामणकर नाका स्थित सचिन अपार्टमेंट, पठारे कंपाउंड में हुई। शिकायतकर्ता महिला अपने घर पर मौजूद थी, तभी उसका पति अतिश रघुवीर चौहान (32) शराब पीकर घर पहुंचा। महिला ने पति को दोबारा दारू पीने से मना किया और इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

ठाणे : पशु कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए तत्काल सुधार की मांग की...

ठाणे : ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के जवाब में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के जिला अध्यक्ष मनोज प्रधान के नेतृत्व में पशु कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से मिलकर सिस्टम में सुधार की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा, जिसमें प्रशासन से आने वाले म्युनिसिपल बजट में जानवरों के लिए नसबंदी, शेल्टर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए खास प्रावधान शामिल करने का आग्रह किया गया।

मुख्य मांगें और चिंताएं

मीटिंग के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा पशु कल्याण इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बड़ी कमियों को उजागर किया: नसबंदी में पारदर्शिता मनोज प्रधान ने ''पकड़ो और छोड़ो'' प्रक्रिया के बारे में चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुत्तों को नसबंदी के लिए उठाया तो जा रहा है, लेकिन इस बात में पारदर्शिता की कमी है कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी मूल जगहों पर वापस छोड़ा जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

कार्यकर्ताओं ने बताया कि शहर में फिलहाल वागले एस्टेट में सिर्फ. एक ही फंक्शनल नसबंदी केंद्र है, जो शहर की जरूरतों के लिए काफी नहीं है। उन्होंने और केंद्र स्थापित करने और इंसान-जानवर के बीच टकराव को रोकने के लिए खास ''फीडिंग जोन'' बनाने की मांग की। शेल्टर होम प्रतिनिधिमंडल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचाए गए कुत्तों के लिए उचित शेल्टर होम की कमी पर जोर दिया, और TMC से खास सुविधाएं बनाने की मांग की।

नाबालिग से दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर महिला के शोषण का आरोप

दो मामलों में अपराध दर्ज

भिवंडी : भिवंडी शहर में महिलाओं और बच्चों से जुड़े दो अलग-अलग गंभीर मामलों के सामने आने के है। के बाद पुलिस ने संबंधित थाना क्षेत्रों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पहला मामला भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग साथ कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया पुलिस के अनुसार 3 फरवरी की दोपहर करीब 1.15 बजे कामतघर स्थित एक चॉल में आरोपी राजकुमार ओमप्रकाश भारती (25) पर घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग पीड़िता की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा

मुंबई : रोहित शेट्टी फायरिंग केसः पुणे से मुंबई तक फैला नेटवर्क, शुभम मास्टरमाइंड, हथियार सप्लाई का खुलासा

मुंबई : फिल्म निमार्ता-निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर 31 जनवरी की रात हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन सेल की जांच से लगातार खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को पता चल गया है कि यह हमला कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि पुणे से मुंबई तक फैले एक सुनियोजित नेटवर्क की साजिश थी। घटना की रात करीब 12.45 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने रोहित शेट्टी के शेट्टी टॉवर की ओर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस समय रोहित घर पर मौजूद थे। सीसीटीवी में साफ दिखा कि काले जैकेट और सफेद पैंट में आए शूटर ने पिस्टल से 5 राउंड फायर किए और फिर स्कूटर से भाग गए। फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए, लेकिन हमलावर फरार हो गए।

जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल स्कूटर पुणे से लाई गई थी। पुलिस ने इसे बाद में विले पार्ले इलाके से लावारिस हालत में बरामद किया। मौके से 5 खाली कारतूस और कांच के टुकड़े भी जब्त किए गए। अब तक कुल पांच लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये सभी पुणे के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, तीन मैगजीन, एक एयरगन और मोबाइल फोन बरामद किए। जांच में पता चला कि आरोपी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे और वारदात के बाद चैट डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की। मुख्य आरोपी शुभम लोणकर को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। .पुलिस के मुताबिक, शुभम ने ही साजिश रची, शूटर को स्कूटर, हथियार और पैसे की व्यवस्था करवाई। शुभम लोणकर और असली शूटर अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं। मामले को लेकर जुहू पुलिस ने सबसे पहले मामला दर्ज किया था, लेकिन अब जांच एंटी एक्स्ट्रॉर्शन सेल को सौंपी गई है। हथियार सप्लाई का एंगल भी खुल गया है। गिरफ्तार आरोपी स्वप्निल सकट के घर से मिले हथियार आरोपी आसाराम फासले ने शुभम लोणकर के कहने पर उपलब्ध कराए थे। इसी आधार पर आसाराम को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि यह मामला खंडणी या पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। जांच अभी जारी है और जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है।

मुंबई : बेलासिस फ्लाईओवर तैयार, बस एक NOC बाकी, जानें कब होगा उद्घाटन?

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से पूरे रहे हैं। मुंबई सेंट्रल में बन रहे बेलासिस फ्लाईओवर की सौगात मुंबईकर को जल्द ही मिल जाएगी। बीएमसी ने इस फ्लाईओवर के निर्माण को पूरा कर लिया है। मेयर चुनाव होते ही इस फ्लाईओवर से वाहन फराटा भरने लगेंगे। दक्षिण मुंबई में जहांगीर बोमन बेहरम रोड (पूर्व में बेलासिस रोड) पर बेलासिस ब्रिज मुंबई सेंट्रल, नागपाड़ा और ताडदेव के पूर्व - पश्चिम से जोड़ने वाले क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण लिंक है।बीएमसी को अब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने एनओसी मिलनी बाकी रह गई है। बीएमसी ने इस फ्लाईओवर पर साउंड बैरियर भी लगा दिए हैं। 15 फरवरी तक इस फ्लाईओवर के खुल जाने की उम्मीद

है। पुराना बेलासिस ब्रिज 1893 में बनाया गया था। यह ब्रिज कुल 333 मीटर लंबा है।

चार महीने पहले बना फ्लाईओवर

बीएमसी में अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर ने इस पुल परियोजना स्थल का व्यक्तिगत दौरा कर निरीक्षण किया। तडदेव-नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों को जोड़ने वाले बेलासिस फ्लाईओवर का अंतिम कार्य मात्र 15 महीने में पूरा हुआ है। इस ब्रिज के काम को पूरा करने की डेडलाइन अप्रैल, 2026 तय की गई थी। ऐसे चार महीने पहले ही इस ब्रिज को बना लिया गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह बेलासिस फ्लाईओवर ब्रिटिश-युग के पुल की जगह लेगा। पुराने पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। इटउ ने पुल के पुनर्निर्माण का काम 1 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया था।

सिर्फ NOC ही रह गई बाकी

बीएमसी को ब्रिज डिपार्टमेंट, रेलवे अथॉरिटी, संबंधित वार्ड ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ा। बेलासिस पुल के पुनर्निर्माण के कारण दो सालों से प्रभावित पूर्व-पश्चिम परिवहन सुविधा बहाल करने के लिए तैयार है। बेलासीस पुल लागू होने के बाद जहांगीर बोमन बेहरम रोड, दादासाहेब भडकमकर रोड (ग्रेंट रोड), खासकर पठ्ठे बापूराव रोड और महालक्ष्मी स्तनाक पुल पर यातायात जाम कम होगा। बीएमसी के अनुसार फिनिशिंग का काम 6 जनवरी, 2026 को पूरा हो गया था।

विकलांग महिला के प्रेग्नेंसी केस में 17 पुरुषों का DNA टेस्ट हुआ, पिता का DNA मैच हुआ...

मुंबई : मुंबई में गैंगरेप की एक घटना में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 20 साल की मानसिक रूप से कमजोर महिला के गैंगरेप के मामले में एक नया एंगल सामने आया है। प्रेग्नेंट लड़की के करीब रहने वाले 17 लोगों का DNA टेस्ट किया गया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में लड़की के पिता का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कैफे परेड पुलिस ने इस मामले में पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, पिछले साल अक्टूबर में कोमा एंड एबल हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन को एक फोन कॉल आया था। बताया गया कि 20 साल की एक मानसिक रूप से कमजोर महिला उनके हॉस्पिटल में थी। उसे पेट में दर्द हो रहा था और वह पांच महीने की प्रेग्नेंट पाई गई। हालांकि, पता चला कि लड़की के साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया था। चूंकि उससे सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की।

उसके जान-पहचान वाले 16 लोगों के DNA सैंपल लिए गए। इसमें उसके पिता, परिवार के सदस्य और पड़ोसी शामिल थे।

पुलिस ने महिला का गर्भपात करवाया। उसके भ्रूण से उठअ सैंपल लिया गया। इसे कलिना की फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया। रिपोर्ट 27 जनवरी को आई। पता चला कि पीड़िता के भ्रूण से लिए गए उठअ सैंपल पिता के उठअ से मैच करते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इसी मामले में कफ परेड झुग्गी बस्ती के दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था।

किसी को जानकारी की कमी के कारण कानूनी मौकों से वंचित किया जाता है, तो यह अन्याय होगा - मुंबई हाई कोर्ट

मुंबई : किसी को जानकारी की कमी के कारण कानूनी मौकों से वंचित किया जाता है, तो यह अन्याय होगा। इसलिए, संबंधित लोगों को कानूनी मौकों की उपलब्धता के बारे में जागरूक करें। उन्हें कानूनी मौकों से वंचित न होने दें, यह आदेश मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दिया है।

चंद्रपुर जिले के नागलोन के रहने वाले प्रोजेक्ट पीड़ित अमोल धवास को शुरूआती जांच में बुनकर की नौकरी के लिए मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया गया था। उनके पास उस फैसले के खिलाफ 30 दिनों के अंदर अपीलीय मेडिकल बोर्ड में अपील करने का कानूनी मौका था।

हालांकि, जानकारी की कमी के कारण, वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। पांच साल बाद इस मौके के बारे में पता चलने पर, उन्होंने अपीलीय मेडिकल बोर्ड से संपर्क करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी को आवेदन किया।

हालांकि, अपील में देरी के कारण 7 अक्टूबर 2022 को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे के सामने सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए याचिका मंजूर कर ली और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के आदेश को रद्द कर दिया।

टपोरी फटके

भारत टैक्सी आ गयेला है..

ओला - उबर का वाट लगनेवाला है

जितेन्द्र कनौजिया

पैले काली- पीली का नाटक चलते था। उन लोग का भाड़ा मना करने से सब्बी लोग कंटाल गयेला था। रिक्शा वाले का पन बोईच नाटकी रहने का। फिर ओला-उबर टैक्सी आया, तो इन लोग का नाटकी थोड़ा कम हो गया। मेट्रो ट्रेन चालू हुआ, तो और थोड़ा ठंडा हो गया। पब्लिक पन सोचा के मस्त हो गयेला है। अब्बी टैक्सी वाले के किरकिर से फुर्सत मिलेगा। करके ओला- उबर टैक्सी ने हर जागे पे अच्छा कस्टमर बना डाला। धंदा चौपट होने लगा काली - पीली का।

लेकिन नया नाटकी चालू क्या हो गया? येईच टैक्सी वाले ओला- उबर में घुस गया और इन लोग का धंदे का पन वाट लगाना चालू कर डाला। फिर इन लोग ने पन पब्लिक को भाड़ा मना करने का चालू कर डाला। पब्लिक बैतागने लग गया। रोज दादागिरी बढ़ने लग गयेला था। सुबे और शाम का टाइम में भाड़ा डबल करने का सिस्टम कर डाला। अपने हिसाब से भाड़ा माँगने का शुरू हो गया। पैले तो इन लोग को अच्छा खासा आदत लगा डाला , फिर भाड़े का दादागिरी करने लग गया। इन सबके बीच में रैपिडो बाइक भी आ गयेला है। अब्बी भोत सिंगल लोग उससे जा रैला है। क्या करेगा, पब्लिक को अपना काम तो निकालना पड़ेगा ना? साला ऑफिस जाने का या कुछ काम से बाहेर जाने का बोलेगा, तो सरदर्द हो गयेला है। बिंदास मनमाना कारभार चल रैला है, बोलने वाला कोई नहीं। पब्लिक राम भरोसे चल रैला है। फुलटू लूटम लाट चल रैला है।

ये सब देखके सरकार को पन समज में आ रैला था के अपना पब्लिक को जबरदस्ती लूटने का कार्यक्रम चल रैला है। इसके लिए सरकार ने सीरियस होकर भारत टैक्सी लॉन्च कर डाला। ये टैक्सी ओला - उबर की मजबूत वाट लगाने वाला है। इसका भाड़ा भी कम रहनेवाला है और सुबे - शाम को भाड़ा पन नहीं बढ़ानेवाला है। अब्बी तो ये दो - तीन जागे पे शुरू हुयेला है। आनेवाला टाइम पे अक्खा इंडिया में शुरू होनेवाला है। अपना मुंबई में जिस दिन चालू हुआ ना, तो देखना ये ओला - उबर वाला अपना दुकान बंद कर डालेगा या तो इज्जत में धंदा करेगा। भारत टैक्सी का कस्टमर बनेगा ना भाय लोग?